

औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले ‘देशद्रोही’ हैं : एकनाथ शिंदे



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ठाणे/भाषा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो लोग अब भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं, वे “देशद्रोही” हैं। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी और लोगों पर अनेक अत्याचार किए थे। शिंदे ने कहा कि दूसरी ओर, मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक “दैवीय शक्ति” थे, जो वीरता, बलिदान और हिंदुत्व की भावना के लिए डटे रहे।

शिंदे ने सोमवार रात ‘शिव जयंती’ के अवसर पर ठाणे जिले के डोंबिवली क्षेत्र के घरदा चौक पर शिवाजी महाराज की अश्वचारीही प्रतिमा का

अनावरण करने के अवसर पर यह बात कही। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा उनकी विरासत, उनके साहस और नेतृत्व क्षमता के सम्मान में स्थापित की गई है। शिवसेना प्रमुख की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब की क़ब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग को लेकर बवाल मचा हुआ है।

इस बीच, सोमवार शाम मध्य नागपुर के चिटनिस पार्क इलाके में तब हिंसा भड़क उठी जब अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान एक समुदाय का धर्मग्रंथ जलाया गया। पुलिस पर पथराव किया गया जिससे छह आम नागरिक और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। शिंदे ने यहां शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में कहा कि शिवाजी महाराज न केवल हिंदुत्व और भारतीय गौरव के प्रतीक थे, बल्कि वह “लोकतंत्र के आविष्कारक” भी थे।

नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित थी, औरंगजेब का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : विहिप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नागपुर/भाषा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलवार को कहा कि वह औरंगजेब का महिमामंडन करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी और दावा किया कि एक दिन पहले नागपुर में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। विहिप के विदर्भ प्रांत के मंत्री देवेश मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन को झड़पों के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करना चाहिए।

मिश्रा ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि नागपुर में विहिप और बजरंग दल के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक पंक्तियां लिखी हुई चादर जलाई गईं, जिससे हिंसा भड़की।



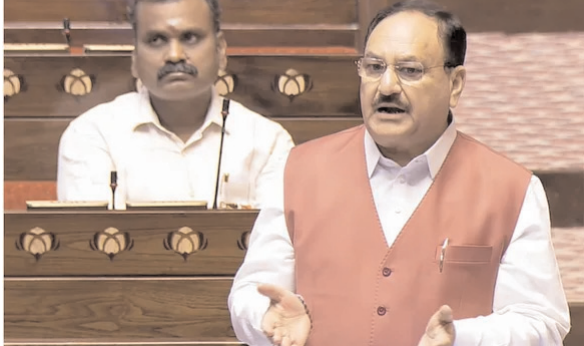
पुलिस ने बताया कि मुगल शासक औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें कई मकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

मिश्रा ने कहा, “हम औरंगजेब का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया गया, सिवाय

लोग अभी भी औरंगजेब का महिमामंडन करते हैं।”

मिश्रा ने आरोप लगाया कि नागपुर में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने अपराधियों पर रासुका लगाने और पुलिस द्वारा प्राथमिकियों में नामजद आरोपियों के घरों को बहाने की मांग की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए “आंदोलन” जारी रहेगा। विहिप के धर्मप्रसार प्रमुख (विदर्भ प्रांत) राजकुमार शर्मा ने दावा किया कि चिटनिस पार्क के सामने स्थित एक मस्जिद से अपील की गई थी, जिसके कारण सोमवार को भीड़ एकत्र हो गई। उन्होंने मस्जिद के ट्रस्टियों और संबंधित मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

शर्मा ने कहा, “हमने (नागपुर) पुलिस आयुक्त और (जिले के) प्रभारी मंत्री से अनुरोध किया है कि वे अपराधियों पर रासुका के तहत मामला दर्ज करें।”



मातृ मृत्यु दर 2014-16 से 33 अंक घटकर 2018-20 में 97 हो गई : नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि भारत ने 2020 तक मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को घटाकर, प्रति लाख जीवित जन्म पर 100 करने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2030 तक एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 का एसडीजी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।

उच्च सदन को एक प्रश्न के उत्तर में नड्डा ने बताया कि भारत के महा पंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार, देश का वर्तमान मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर 97 है। उन्होंने

कहा कि एमएमआर 2014-16 में 130 था जो 2018-20 में 97 हो गया। इस प्रकार एमएमआर में 33 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। नड्डा ने कहा, “भारत ने 2020 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 एमएमआर का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 2030 तक एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 का एसडीजी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।” उन्होंने कहा कि भारत में एमएमआर में 83 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसमें 42 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह, भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) में 75 प्रतिशत की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर पर 58 प्रतिशत की गिरावट से अधिक है।

मेबैक के लिए शीर्ष पांच बाजारों में शामिल हो सकता है भारत : मर्सिडीज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



उदयपुर (राजस्थान) मर्सिडीज-मेबैक के प्रमुख डेनियल लेस्को ने मंगलवार को कहा कि भारत में मेबैक श्रृंखला के वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच बाजारों में शामिल होने की क्षमता है, क्योंकि देश में उच्च श्रेणी के लक्जरी वाहनों की मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। मर्सिडीज-बेंज ने पिछले साल

भारत में मेबैक खंड की बिक्री में 140 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की और यह 500 से अधिक इकाइयों तक पहुंच गई। लक्जरी कार विनिर्माता ने मेबैक एसएल 680 मोनोग्राम श्रृंखला को पेश कर देश में अपनी श्रृंखला का विस्तार किया है। इसकी कीमत 4.2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस मॉडल की आपूर्ति अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।

लेस्को ने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि भारत इस ब्रांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि यहां लोगों में ‘लक्जरी’ जीवनयापन की भावना विकसित हो रही है। उन्होंने कहा, “ भारत

पहले से ही वैश्विक स्तर पर मेबैक के लिए शीर्ष 10 बाजारों में शामिल है और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि की संभावना है। हमारा मानना ​​है कि भारत में निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर मेबैक के लिए शीर्ष पांच बाजारों में शामिल होने की क्षमता है।” लेस्को ने बताया कि वर्तमान में चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे बाजार वैश्विक स्तर पर ब्रांड की बिक्री में अग्रणी हैं।

भारत को ब्रांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “ हमें यह देखकर बेहद खुशी हुई कि भारतीय ग्राहकों में ब्रांड की छवि कितनी अच्छी है। यह बिक्री के आंकड़ों में भी झलकता है।”

मर्सिडीज-बेंज इंडिया, मर्सिडीज-मेबैक मॉडल का विविध खंड पेश करती है, जिसमें एस 680 नाइट सीरीज, जीएलएस 600 नाइट सीरीज, ईक्वएस 680 नाइट सीरीज, ईक्वएस एसयूवी और स्थानीय रूप से निर्मित एस 580 लिमोसिन शामिल हैं।

रेलवे में पिछले एक दशक में पांच लाख लोगों को रोजगार दिया गया, आरक्षण का ध्यान रखा गया: वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में रोजगार और रेल भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पिछले एक दशक में रेलवे में पांच लाख रोजगार दिए गए हैं और इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है।

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर निचले सदन में हुई चर्चा पर जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में रेलवे में पांच लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और आज भी एक लाख लोगों के लिए रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने दावा किया कि देश में रेल भर्ती की परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक एवं अन्य व्यवधानों के संचर कराई जा रही हैं। रेलवे भर्ती की परीक्षाओं का केंद्र



अभ्यर्थी के गृह क्षेत्र से बाहर होने संबंधी मुद्दे पर कुछ सदस्यों की चिंताओं का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि गृह क्षेत्र से बाहर परीक्षा केंद्र रखने की नीति देशभर में लागू है ताकि परीक्षा की शुचितता पर प्रश्न नहीं उठे। उन्होंने कहा कि रेलवे में सभी पांच लाख नौकरियों में आरक्षण के सभी नियमों और कानूनों का पालन किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में 60 साल में पहली बार वार्षिक कलेंडर की व्यवस्था की गई है।

सिंगापुर, मातृ तलाश रहे हैं ‘ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर’ पर समझौते की संभावना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिंगापुर/भाषा। सिंगापुर और भारत ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (जीडीएससी) के लिए आशय पत्र (एलओआर) पर हस्ताक्षर करने की संभावना तलाश रहे हैं, जिससे भारतीय समुद्री क्षेत्र को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद है।

पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अगले सप्ताह सिंगापुर यात्रा के दौरान आशय पत्र पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सोनोवाल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर समुद्री सप्ताह (एसएमडब्ल्यू) में भाग लेने की उम्मीद है, जो 24 से 28 मार्च तक यहां आयोजित किया जा रहा है।

सिंगापुर समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण (एमपीए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तेओ इंग दीह ने कहा, “ हम शुरुआत के तौर पर भारत के साथ आशय पत्र पर सहमति बनाने के बारे में विचार रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर हम अब भी काम कर रहे हैं।” सिंगापुर समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण (एमपीए) सप्ताह भर चलने वाले समुद्री कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है।

लोकतांत्रिक देश को पुलिस राज्य की तरह काम नहीं करना चाहिए : उच्चतम न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने जांच पूरी होने के बावजूद निचली अदालतों द्वारा “कम गंभीर मामलों” में जमानत याचिकाएं खारिज किये जाने पर निराशा जतायी है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को पुलिस राज्य की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियों बिना किसी वास्तविक कारण के लोगों को हिरासत में लेने के लिए मनमानी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। दो दशक पहले छोटे मामलों में जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालयों तक शायद ही कभी पहुंचती थीं, शीर्ष अदालत

है, खासकर छोटे उल्लंघनों से जुड़े मामलों में। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक आरोपी को जमानत दे दी जो धोखाधड़ी के एक मामले में दो साल से अधिक समय से हिरासत में था। जांच पूरी हो जाने और आरोपपत्र दायर हो जाने के बावजूद, आरोपी की जमानत याचिका निचली अदालत और गुजरात उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 2022 में जांच एजेंसियों पर उन संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें हिरासत की आवश्यकता न होने पर अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है। इसने निचली अदालतों से यह सुनिश्चित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का भी आग्रह किया था कि जमानत निष्पक्ष और समय पर दी जाए।

ओबीसी आरक्षण पर तेलंगाना ने रास्ता दिखाया, यही पूरे देश की जरूरत: राहुल



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा को क्रांतिकारी कदम करार देते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य ने रास्ता दिखाया है और यही पूरे देश की जरूरत है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी समुदाय के लिए 42%

आरक्षण सुनिश्चित करने की घोषणा की। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, “कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार तथा राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया है।” उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह वास्तविक एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। कांग्रेस नेता के अनुसार, जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे सबकी बेहदरी सुनिश्चित हो।

देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बदहाल, विभिन्न मानकों पर भारत पड़ोसी देशों से भी पीछे : विपक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति बदहाल है और विभिन्न मानकों पर भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इसके साथ ही सदस्यों ने सुझाव दिया कि

सरकार को बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए। तुषमूल कांग्रेस के सुखेंद्रु शेखर राय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कारकाज पर उच्च सदन में हुयी चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ आर्थिक भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस आर्थिक भेदभाव के खिलाफ केंद्र को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न शर्तों को पूरा करने के



बाद भी पश्चिम बंगाल को मनरेगा सहित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राशि नहीं दी जा रही है। राय ने फर्जी दवाइयों के खिलाफ अभियान चलाए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि विभिन्न

उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी, सितारगंज व काशीपुर में 15 मदरसे सील किये

रुद्रपुर/भाषा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही और अधिकारियों ने सितारगंज और काशीपुर में ऐसे 15 मदरसों को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से

नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिह ने बताया कि काशीपुर में 12 और सितारगंज में तीन मदरसे सील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से

पंजीकृत न होने वाले मदरसों को सील किया जा रहा है। बिह ने बताया कि मदरसों के पास अन्य आवश्यक दस्तावेज भी नहीं हैं।

इस महीने की शुरुआत में देहरादून जिले में पंद्रह मदरसों को अनिवार्य मंजूरी न होने के कारण सील कर दिया गया था।

बिरला ने दिल्ली विस को ‘आदर्श विधानसभा’ के रूप में विकसित करने का किया आह्वान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को एक “आदर्श” विधानसभा के रूप में विकसित करने का आह्वान किया और नवनिर्वाचित विधायकों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को सीखने अपील की। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिरला ने कहा कि लोगों को विधायकों और राष्ट्रीय राजधानी की नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

दिल्ली को ‘लघु भारत’ का रूप बताते हुए बिरला ने कहा कि यहां सभी राज्यों से विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों



के लोग आते हैं, और उनकी अलग-अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों की अपने विधायकों और नई सरकार से उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने के तरीकों को सीखने में सहायक होगा। विधानमंडलों को सार्थक संवाद का मंच बताते हुए बिरला ने कहा, “सदन में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होना

चाहिए तथा असहमति को गंभीरतापूर्ण ढंग से तथा सार्थक संवाद के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए।” उन्होंने सदस्यों से सार्वजनिक जीवन में आचरण तथा नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। बिरला ने कहा, “लोकतंत्र का आधार संवाद और आम सहमति है, इसलिए संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए।”



सरकारी टेकों में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी विधेयक विधानसभा में पेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक सरकार ने सरकारी टेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया। राज्य के संसदीय एवं विधि मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कर्नाटक सरकारी खरीद

में पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश किया। राज्य मंत्रिमंडल ने गत शुक्रवार को कर्नाटक सरकारी खरीद में पारदर्शिता अधिनियम (केटीपीसी) में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत दो करोड़ रुपये तक के कार्यों और एक करोड़ रुपये तक के माल/सेवा अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री

सिद्धरामय्या ने सात मार्च को पेश किए गए 2025-26 के बजट में की थी। वर्तमान में, कर्नाटक के सरकारी टेकों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 24 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)-श्रेणी 1 के लिए चार प्रतिशत और ओबीसी-श्रेणी 2ए के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण लागू है। मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण के साथ ओबीसी की

श्रेणी 2बी में शामिल करने की मांग की गई थी। राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकारी टेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को "असंवैधानिक दुस्साहस" करार दिया है। इसने इसे रद्द कराने के लिए अदालत का रुख करने सहित सभी स्तरों पर विरोध करने का संकल्प लिया है।

विधानसभा में मंत्रियों की अनुपस्थिति सरकार की गरिमा को कमतर करती है : यूटी कादर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यू टी कादर ने मंगलवार को सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सरकार की गरिमा को कमतर करती है। उन्होंने जानना चाहा कि अगर मंत्री विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो सकते और समय पर चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकते तो वे अपने पदों पर क्यों बने रहना चाहते हैं। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा सरकार की आलोचना किये जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कादर ने कहा कि कुछ को छोड़कर ज्यादातर मंत्री सदन में अनुपस्थित थे। उन्होंने आसन से कहा, "मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए, कोई भी उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंत्री इस सरकार की गरिमा को कमतर कर रहे हैं। मंत्री अच्छे काम करने के बावजूद, समय पर सदन में नहीं आकर सरकार का असम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम को सदन में कृष्णा बायरे गौड़ा के अलावा कोई अन्य



मंत्री मौजूद नहीं थे तथा उनकी उपस्थिति से कुछ विधायी कामकाज हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्चर्य जताते हुए कहा, जब वे सदन में समय पर आना नहीं चाहते तो मंत्री क्यों बनें? किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो समय पर आ सके (मंत्री के रूप में)। वे मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वे विधानसभा में जवाब नहीं दे सकते या सरकार की ओर से खड़े नहीं हो सकते, क्या किया जा सकता है? कादर ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना खारिज नहीं की जा सकती है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल के सदन में पहुंचने पर कादर ने कहा, जब मुख्यमंत्री सदन में होते हैं तो सभी मंत्री आते हैं। इसकी

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री चीजों को संभाल सकते हैं। जब मुख्यमंत्री सदन में नहीं होते हैं, उन्हें (मंत्रियों को) आना चाहिए। जब वह (मुख्यमंत्री) यहां हैं तो (मंत्रियों) के आने और जब वह (मुख्यमंत्री) सदन में नहीं हैं तो चले जाने का क्या फायदा है? इसके पहले, नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की शुरुआत की तो भाजपा विधायक सुनील कुमार ने सत्तापक्ष की खाली सीट की ओर इशारा करते हुए सरकार की आलोचना की। विपक्ष के नेता अशोक ने कहा कि मंत्रियों के पहुंचने तक सदन को स्थगित रखा जाए और उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया कि वह सरकार के मुख्य सचेतक को निर्देश दें कि मंत्रियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए या फिर उन्हें पद से हटा दें। इसके जवाब में, मुख्य सचेतक अशोक पट्टन ने कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें (मंत्रियों को) फोन किया और मुझे बताया गया कि वे कुछ देर में आएंगे... इसके बाद खादर ने सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया।

प्रदर्शन



नव कर्नाटक एमआरडब्ल्यू/बीआरडब्ल्यू/युआरडब्ल्यू विकासचेतना गौरवधान कार्यकर्ता संघ के सदस्य मंगलवार को बेंगलूर के फ्रीडम पार्क में वित्त विभाग के पास लंबित न्यूनतम वेतन फाइल को मंजूरी देने और इसके क्रियान्वयन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए।

बम की आशंका के बीच तिरुवनंतपुरम जिलाधिकारी कार्यालय पर मधुमक्खियों का हमला

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के तिरुवनंतपुरम जिलाधिकारी कार्यालय के पाइप में विस्फोटक लगाए जाने की मंगलवार को धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जब इमारत की तलाशी ले रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में करीब 70 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिलाधिकारी

कार्यालय को दोपहर के समय ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जो बाद में झूठी निकली। तिरुवनंतपुरम की जिलाधिकारी अनु कुमारी ने संवाददाताओं को बताया, पहले हमें बम की सूचना मिली। हमें एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि यहां पाइप में आरडीएक्स लगाया गया है। हमने पुलिस से जांच करने को कहा। उन्होंने जांच की और कुछ

नहीं मिला। उन्होंने बताया, इस बीच, जब हम लोगों को बाहर निकाल रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने हम पर हमला कर दिया। हमारे कई कर्मचारियों को डंक मार दिया। हम उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले गए। अनु ने बताया कि बम विस्फोट जैसी संभावित घटना के बीच मधुमक्खियों का हमला अप्रत्याशित था।

बीएमआरसीएल ने भर्ती विज्ञापन वापस लिया, कन्नड भाषा की अर्हता में ढील देने का हो रहा था विरोध

बेंगलूर/दक्षिण भारत। बेंगलूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने कन्नड भाषा का अनिवार्य ज्ञान रखे बिना अनुबंध के आधार पर 50 ट्रेन ऑपरेटरों (लोको पायलटों) की भर्ती करने के अपने फैसले को भारी विरोध के बाद वापस ले लिया है। बीएमआरसीएल ने 12 मार्च को पांच साल के कार्यकाल के लिए ट्रेन ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। पात्रता मानदंड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और किसी भी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में तीन साल का अनुभव शामिल था। विज्ञापन में हालांकि, गैर-कन्नड उम्मीदवारों को कन्नड पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए एक वर्ष का समय देने संबंधी प्रावधान करने की भारी आलोचना हुई थी। उप मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार ने सोमवार रात अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर विज्ञापन नोटिस को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा, हाल ही में बीएमआरसीएल द्वारा ट्रेन ऑपरेटर (लोको पायलट) के लिए आमंत्रित विज्ञापन में न्यूनतम तीन साल अनुभव की अर्हता को वापस ले लिया गया है।

इंडी ने बेंगलूर में सोरोस की फंडिंग एजेंसी और निवेश शाखा पर छापेमारी की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बेंगलूर। प्रवर्तन निदेशालय ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित "निजी वित्तपोषण एजेंसी" ओएसएफ और इसकी निवेश शाखा ईडीएफ के खिलाफ कथित विदेशी मुद्रा विनियम कानून के उल्लंघन मामले में मंगलवार को बेंगलूर में छापेमारी की कार्रवाई की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) और इकनॉमिक डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) के कुछ लाभार्थियों के आठ परिसरों की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी ली गई। इनमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों से जुड़े लोग और एस्पाडा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने बताया कि एस्पाडा इन्वेस्टमेंट्स भारत में सोरोस ईडीएफ (एसईडीएफ) का निवेश सलाहकार या कोष प्रबंधक है। यह मॉरीशस की एक इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली "सहायक कंपनी" है। उन्होंने बताया कि एसईडीएफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (ओएसएफ) की प्रभाव निवेश शाखा है। यह जांच सोरोस की दो संस्थाओं द्वारा कथित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने तथा कुछ लाभार्थियों द्वारा फेमा दिशानिर्देशों का कथित उल्लंघन करते हुए इन निधियों का उपयोग करने से संबंधित है। ईडी सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ओएसएफ को 2016 में गृह मंत्रालय ने पूर्व संदर्भ श्रेणी में रखा था और इसे भारत में गैर सरकारी संगठनों को 'अनियंत्रित तरीके से' दान देने से 'प्रतिबंधित' किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध को निष्प्रभावी करने के लिए ओएसएफ ने भारत में सहायक कंपनियां बनाईं और एफडीआई

नईदिल्ली/बेंगलूर। केन्द्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का यह बयान कि उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जमीन नहीं चुराई, इसका मतलब यह है कि उन्होंने चोरी नहीं की। हर चीज के लिए एक मापदंड और रिकॉर्ड होता है, है न? इसका सिद्धरामय्या और शिवकुमार से क्या लेना-देना है? कुमारस्वामी को क्यों चिंतित होना चाहिए? डीसीएम डीके शिवकुमार ने इसका खंडन किया है। शिवकुमार ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। कुमारस्वामी के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि वे कांग्रेस के निशाने पर हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा,



मैंने और सिद्धरामय्या ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने अदालत के निर्देशानुसार कानून के अनुसार सब कुछ किया है। हम केंथगनहल्ली समाचार पर नहीं गए। हमें इस मामले की जानकारी भी नहीं है। किसी ने इस बारे में जनहित

याचिका दायर की है। यह कई सालों से चल रहा है। अदालत ने भूमि कर के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। हमने मीडिया में इसके बारे में पढ़ा है। अधिकारियों ने जाकर जमीन की पैमाइश की है क्योंकि अदालत ने कार्रवाई करने के लिए समय सीमा दी है। उन्होंने कहा, मैंने व्हाट्सएप पर आई खबर देखी। क्या अधिकारी बिना नोटिस दिए नाप सकते हैं? नाप तो शुरू से ही हो गई थी। उनके कर्मचारियों ने पत्र लिखकर क्यों कहा कि अगर उनके पास अतिरिक्त जमीन है तो उसे वापस ले लें? यह पता नहीं है कि उन्होंने कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया है। अब हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे बारे में पहले क्या कहा था।

कर्नाटक में दलित नेताओं की बैठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और कांग्रेस विधायक के.एच. मुनियप्पा ने हाल ही में दलित नेताओं की एक अहम बैठक के बाद कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की गई है। मुनियप्पा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ निर्देश दिए हैं, जिसके तहत एससी/एसटी समुदायों की जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाएगा। कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जस्टिस नागमोहन दास को नियुक्त किया गया है, जो इस पर विस्तृत अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मंत्री ने कहा कि यह पूरा मामला 2011 की जनगणना पर आधारित है। सरकार को जनगणना से जुड़े मुद्दों की जांच करनी है ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सभी अनुसूचित जाति समूहों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होने चाहिए। इसके लिए जरूरी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और आयोग को सौंपे जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री एच.सी. महादेवप्पा को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। मुनियप्पा ने कहा कि

महादेवप्पा इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनावी तैयारियों की योजना भी बनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री को बदलने की कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, यह हमारे हाथ में नहीं है। यह फैसला हाईकमान को करना है। इस पर बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसे लेकर अनावश्यक चर्चा से बचना चाहिए। मुनियप्पा ने भरोसा जताया कि जस्टिस नागमोहन दास की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ठोस कदम उठाएगी। इससे पहले भी कर्नाटक में एससी/एसटी आरक्षण को लेकर कई चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इस फैसले से दलित समुदायों में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग(सीएमजी) इसरो-मुख्यालय, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी ई एल रोड, बेंगलूर - 560094 फोन : 080-22172476 / 2479 / 2033 फैक्स : 080-23513126	
संक्षिप्त ई-निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के उम्मेदरों से निम्नलिखित कार्यों के लिए नगद दर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित आमंत्रित की जाती हैं।	
एनआईटी सी	सीएमजी/इसरो-मुख्यालय/सी/सी/03/पी/एबी/2024-25 दिनांक 17.03.2025
कार्य का नाम	अंतरिक्ष भवन, इसरो मुख्यालय, बेंगलूर में मुख्य भवन के गलियारों के लिए मेटल टाइल फास्स सीलिंग प्रदान करना सिविल और विद्युत कार्य
निविदा का अनुमानित मूल्य	रु. 66.24 लाख
कार्य समापन अवधि	छह (06) माह
निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	17.03.2025 को 18.10 बजे से 06.04.2025 को 23.59 बजे तक
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	09.04.2025 को 15.30 बजे तक
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय (तकनीकी बोली)	09.04.2025 को 16.00 बजे से
अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	रु. 1,32,480/-
पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए, इच्छुक निविदाकर्ता कृपया वेबसाइट www.isro.gov.in/tenders.html और www.tenderwizard.com/ISRO पर निविदा मुक्त दृश्य पर विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) देखें। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) और निविदा दस्तावेज ई-टेंडरिंग वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। www.tenderwizard.com/ISRO ह/- समूह प्रमुख- सीएमजी	



वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा भारत : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को चूरू में विकास कार्यक्रमों और जनहित की योजनाओं की समीक्षा की। बागडे ने कहा कि भारत वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और देश सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है। यहां के शूरवीरों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की है। हम सभी

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में सहयोग दें। हमारी पीढ़ी को बौद्धिक रूप से मजबूत करें। हम बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो देश खुशहाल होगा। राज्यपाल बागडे ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर समुचित दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल बागडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का बेहतरीन क्रियान्वयन करें और शिक्षा नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दें तथा शैक्षिक सुदृढीकरण के लिए संकल्पित रहें। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के

दौरान बड़ी संख्या में पौधे लगाए तथा घने जंगल के रूप में विकसित करें। पारिस्थितिकी व पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अधिकाधिक वृक्षारोपण करें तथा प्रयास करें कि छायादार पौधे लगाएं। इसी के साथ राज्यवृक्ष खेजड़ी का संरक्षण, संवर्द्धन करें।

बागडे ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास को गति मिले और अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। यहां की क्षेत्रीय विशेषताओं को बढ़ावा दें ताकि रोजगार के बेहतरीन अवसर सृजित हों। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि

पीएम सूर्यचर योजना में किसानों व आमजन को प्रेरित करें। पीएम कुसुम योजना में किसानों को प्रेरित करते हुए खेतों में अधिकतम सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएं ताकि काश्त में काश्तकारों को संबल मिल सके। किसानों को उनकी फसल को खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने के लिए प्रेरित करें तथा कृषि, विपणन, उद्यानिकी व बैंकों आदि की विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करें। जेजेएम में सभी गांवों में पेयजल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें तथा पेंडिंग कनेक्शन पूरे करें। बागडे ने कहा कि राजीयिका महिलाओं को विभिन्न ऋण

योजनाओं में लाभान्वित करें और प्रयास करें कि योजना में ऋण योजना में लाभ का बेहतरीन सूटीलाइजेशन हो। महानरेगा योजना अंतर्गत सुदूर गांवों-दाणियों में सड़कों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें। इसी के साथ महानरेगा में श्मशान व जोहड़ विकास कार्यों पर फोकस करें। वाटरशेड कार्यों में वर्षा जल संरक्षण करते हुए भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास करें। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत करवाते हुए दिशा-निर्देशों की पालना करवाने व बेहतरीन क्रियान्वित के लिए आश्चर्य किया।

भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान है परेशान : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर उसके कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखे जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है परन्तु अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। गहलोत ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि जबकि गेहूँ की अभी कटाई भी नहीं हुई परन्तु गेहूँ की एमएसपी पर खरीद का पंजीयन शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा ने गेहूँ की एमएसपी 2700 रुपये



करने की बात अपने घोषणा पत्र में की थी जो अभी तक पूरी नहीं की है। पहले मूंगफली की सरकारी खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं।

उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों को ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही और ना ही उपज का सही दाम दे पा रही है। ऐसा लगता है राजस्थान के किसानों को भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार की ही भांति अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। राजस्थान के किसान अपने को उपेक्षित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने गेहूँ की एमएसपी 2700 रुपये

दिया है। राजस्थान के किसान अपने को उपेक्षित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने गेहूँ की एमएसपी 2700 रुपये करने की बात अपने घोषणा-पत्र में की थी, जो अभी तक पूरी नहीं की है। पहले मूंगफली की सरकारी खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं। ये सरकार किसानों को ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही और ना ही उपज का सही दाम दे पा रही है। ऐसा लगता है राजस्थान के किसानों को भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार की ही भांति अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। राजस्थान के किसान अपने को उपेक्षित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए।



जनकल्याण को समर्पित होगा राजस्थान दिवस : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में आगामी राजस्थान दिवस (30 मार्च, 2025) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के उपलक्ष्य पर सप्ताहभर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के इन चारों वर्गों को सौगात दी जाएगी। इस पर्व पर जनकल्याण को समर्पित कार्यक्रमों के साथ ही निवेश उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लाकार्पण एवं शिंलायास भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपांश बनाते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर रोजगार उत्सव के माध्यम से

सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही जिला मुख्यालय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह बजट घोषणाओं की अनुपालना में राज्य सरकार कौशल नीति एवं युवा नीति भी लेकर आएगी। विध्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का मेलों का आयोजन तथा किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तान्तरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभाधिक्य एवं विभिन्न महिला समूहों को सी.आई.एफ. राशि का हस्तान्तरण किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश की महिलाओं को इंडवशन कुकटप, कालीबाई भील योजना के अन्तर्गत स्कूटी वितरण एवं विदेकानन्द स्कोरशिप योजना के लाभान्वितों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाएगा।

सरिस्का बाघ अभ्यारण्य को मंगलवार को बंद रखने का आग्रह

जयपुर। राजस्थान के वन्यजीव प्रेमियों ने राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से सरिस्का बाघ अभ्यारण्य को मंगलवार को बंद रखने का अनुरोध किया। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के निकट पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार को सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। उन्होंने मंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि सबसे व्यस्त दिन पर बाघ अभ्यारण्य को खुला रखने से वन्यजीवों की परेशानी बढ़ जाती है। 'सरिस्का टाइगर काउंसेलर' के संस्थापक सदस्य दिनेश दुर्गानी ने पत्र में कहा, अभ्यारण्य को मंगलवार को बंद करने से वन्यजीवों को काफी लाभ होगा क्योंकि इससे मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले तनाव में कमी आएगी। उन्होंने कहा इस बदलाव से पूरे समाह आगंतुकों की संख्या में समानता रहेगी, जिससे बेहतर संरक्षण प्रयास सुनिश्चित होंगे। एक अन्य वन्यजीव प्रेमी ने कहा कि बुधवार को रिजर्व को बंद करने का मौजूदा तरीका रणथंभौर मॉडल का अनुसरण करता है।



उदयपुर के बापू बाजार में एक शोरूम में भीषण आग लगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में उदयपुर के बापू बाजार इलाके में मंगलवार सुबह घड़ियों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि देखते ही देखते आग तीन मंजिला इमारत में फैल गई, जिससे मालिक का परिवार ऊपरी मंजिल पर फंस गया। पुलिस ने बताया कि बाजार के एक हिस्से को खाली करा लिया गया और फंसे हुए परिवार को बचा लिया गया। पुलिस का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास से बड़ी

संख्या में लोगों को हटया गया। उसने बताया कि आग शोरूम वाली इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दूसरी मंजिल तक फैल गई। पुलिस के मुताबिक आपातकालीन बचाव दल को मालिक निकेश तनक पहुंचने के लिए करीब दो घंटे तक मशकत करनी पड़ी, जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ तीसरी मंजिल पर फंसे हुए थे। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस के मुताबिक दो पुलिसकर्मी मालिक के परिवार की मदद के लिए सीढ़ी से चढ़े। उन्होंने परिवार के सदस्यों को बगल की इमारत से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। बाद में आग पर काबू पा लिया गया।



राजस्थान में बिना भेदभाव हो रहे विकास कार्य : प्रेमचंद बैरवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में उम्मीद से बेहतर कार्य हो रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा आज जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लूणी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में बैरवा ने

खींवर विधायक रेवत राम डांग्रा द्वारा विकास कार्यों को लेकर जताई गई नाराजगी पर कहा, राज्य में सबके काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से काम करवा रहे हैं। पत्र लिखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्यमंत्री के पास हर समस्या का समाधान मौजूद है। बाल मुकुंद आचार्य द्वारा लाउडस्पीकर से माइश्रेन और कान संबंधी समस्या उठाने पर उन्होंने कहा कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम संस्कृति और संस्कारों से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा मेस बहिष्कार से जुड़े सवाल पर बैरवा ने कहा, ऐसा कोई बहिष्कार नहीं किया गया, स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं के निपटारे के लिए बुलाई गृह विभाग की बैठक

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिसकर्मियों की पदोन्नति, वेतन, अवकाश संबंधी मांगों सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को गृह विभाग की एक बैठक बुलाई और अधिकारियों को निर्देश दिये। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) आनन्द कुमार ने बताया कि राजस्थान पुलिस बल के कर्मियों और अधिकारियों द्वारा 15 मार्च को होली नहीं मनाने की जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर इस विषय को काफी गंभीरता से लिया गया और पुलिस विभाग में लंबित समस्याओं का स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा को इस बात से भी अवगत कराया गया कि पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी कुछ मांगों पिछले पांच-छह वर्षों से विचाराधीन हैं, जिनमें उनकी पदोन्नति, वेतन, अवकाश संबंधी अनुरोध शामिल हैं। कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया और अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से संबंधित तथा उनके कल्याणार्थ बिंदुओं पर अतिशीघ्र आवश्यक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

भाजपा विधायक ने अजान के लिए लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित करने की जरूरत बताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ज य प उ र / ज ो ध प उ र । राजस्थान के जयपुर में हया महल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सोमवार को कहा कि अजान के लिए लाउडस्पीकरों की आवाज नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेज आवाज से कई लोगों को सिरदर्द और 'माइग्रेन' की समस्या होती है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आचार्य ने कहा कि इन दिनों में (रमजान) जानबूझकर लाउडस्पीकरों की आवाज बढ़ा दी जाती है और कुछ लोगों ने अपने घरों में लाउडस्पीकर लगा लिए हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए और उसे नियंत्रित करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सत्तारूढ़ दल के विधायक आचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के कुछ विधायक अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं,

इसलिए इस तरह की फालतू के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने भी भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि असली मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय वह सिर्फ हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं। भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने यहां संवाददाताओं से कहा, जिनको पीड़ा है, सिर दर्द है, माइग्रेन है तो उन्हें इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इन दिनों में (रमजान) आवाज ज्यादा की जा रही है। कुछ घरों में लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। हमने दो-चार जगहों पर निवेदन किया है कि घर पर लाउडस्पीकर नहीं लगायें। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन जांच करे कि आवाज कितनी होनी चाहिए और कितनी आवाज फिलहाल है। उस आवाज की जांच करने के लिये पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वे मामले की जांच करें। प्रदेश सरकार में विधि एवं विधिक मामलों के मंत्री जोगाराम पटेल से जोधपुर में जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों की तरह लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाएगी।

स्वागत



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटसरा के मंगलवार को उदयपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

बलूचिस्तान की महिला सीमा पार करके आई भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में पाकिस्तान की एक महिला को सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने पकड़ा है। महिला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है। महिला से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में उसे बताया है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार थी और इसलिए पाकिस्तान से भारत आ गई। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के अनुपगढ़ सेक्टर में सोमवार सुबह पाकिस्तानी महिला को पकड़ा गया। बीएसएफ की विजेटा पोस्ट के अधीन पिलर नंबर 362/28 के पास से महिला रात किसी समय भारतीय क्षेत्र में बलूचिस्तान प्रांत के जिला कैच में तहसील तुरबत के गांव दगरी खान में वह पति के साथ रहती थी। लेकिन उसका पति

बीएसएफ के गश्ती दल को पैर के निशान दिखे। इसका पीछा करते हुए उन्होंने महिला को पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि महिला के पास एक मोबाइल फोन मिला है। उसने सोने की बालियां, नोज पिन और चूड़ियां पहनी हुई थीं। देखने में वह समृद्ध परिवार की लग रही है। महिला को अनुपगढ़ में बीएसएफ के मुख्यालय पर लाया गया। कुछ ही देर में श्रीगंगानगर मुख्यालय से बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी अनुपगढ़ सेक्टर में पहुंच गए। बीएसएफ के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू कर दी।

सूत्रों के अनुसार महिला ने अपना नाम हुमायरा बताया है। उसने कहा कि कासिम नाम के एक शख्स से उसका निकाह हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जिला कैच में तहसील तुरबत के गांव दगरी खान में वह पति के साथ रहती थी। लेकिन उसका पति

उसके साथ मारपीट करता था। महिला मूल रूप से कराची की है। हुमायरा ने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। महिला का कहना है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार थी और भारत आने का दूसरा कारण वह इन दिनों बलूचिस्तान में हो रही हिंसा भी है। उसने बताया है कि हिंसा के चलते वह खुद को पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस करती है। इसी कारण वह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वह जान माल का खतरा बताते हुए वापस पाकिस्तान जाने से इनकार कर रही है। उसने कहा है कि यहां जाते ही उसे मार दिया जाएगा। उसने भारत में रहने के लिए शरण मांगी है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां उससे कड़ी पूछताछ करने में लगी हैं। उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। देर शाम तक हुमायरा को बीएसएफ ने पुलिस के सुपुर्द नहीं किया था।

सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों से हो वसूली : गौतम कुमार दक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति की जाए। अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। जिन खरीद केन्द्रों पर पूर्व में अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाए। साथ ही, उनका भुगतान रोकने की कार्यवाही भी की जाए। पीएम सम्मान निधि में दोषियों से वसूली की कार्यवाही की जाए। दक अपेक्ष

बैंक सभागार में राज्य बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं सहित विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

दक ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अकृषि ऋणों की वसूली के लिए अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए ऋणी सदस्यों को नोटिस देने के साथ ही समझावश की जाए। मंत्री ने दक ने एकमुश्त समझौता योजना का झ्रुपट वित्त विभाग से अनुमोदन के लिए शीघ्र भिजवाए जाने तथा योजना का व्यापक

प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने योजना के बारे में सभी ऋणियों को कॉल सेन्टर के माध्यम से सुचित करने के लिए एजेंसी हायर करने के भी निर्देश दिए।

दक ने अप्रैल से शुरू होने जा रही चना-सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर राजफेड अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर को लेकर उप रजिस्ट्रारों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए।



सुविचार

जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चैटबॉट: रटू तोता या दोधारी तलवार?

हाल में जो एआई चैटबॉट अपनी सामग्री के कारण विवादों में रहे, उनके बारे में पढ़कर रटू तोतों की कहानियां याद आती हैं। कुछ तोते ऐसे होते थे (आज भी हैं), जो किसी व्यक्ति को देखते तो मीठे शब्दों से उसका स्वागत करते, भगवान का नाम लेते। कुछ तोते अपने कठोर शब्दों के कारण मशहूर हो गए। वे आते-जाते लोगों पर ऐसी टिप्पणियां करते कि सुनने वाले को गुस्सा आता और अचंभा भी होता। अब ऐसे तोते बहुत कम दिखाई देते हैं। उनकी जगह कुछ चैटबॉट आ गए हैं, जिनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन जगत में उनकी लोकप्रियता नए रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि इन चैटबॉट की बातों पर पूरी तरह यकीन कर लेने के नुकसान भी हैं। 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) के चैटबॉट ग्रीक ने कुछ यूजरर्स को जिस तरह जवाब दिए, उससे हंगामा हो गया। इसके बाद ग्रीक पर शब्दों की मर्यादा, शालीनता और इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले, चीनी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप डीपसीक के नए एआई चैटबॉट द्वारा दिए गए कुछ सवालों के जवाबों की खूब आलोचना हुई थी। कहा गया था कि यह चैटबॉट जवाब देने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से 'हरी झंडी' लेता है! ऐसे चैटबॉट युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वे इनके साथ घंटों बातें कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं, वह कोई जीवित इन्सान नहीं है, लेकिन चैटबॉट को साथ एक लगाव पैदा हो जाता है। आज कई परिवारों में स्थिति यह है कि लोग हमेशा अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त रहते हैं। उन्हें आपस में बातचीत किए महीनों हो गए। पिछली बार खुलकर कब हंसे थे, यह याद नहीं है। क्या ऐसे चैटबॉट परिवारों में विभाजन की रेखा को और गहरी नहीं बना देंगे?

पिछले एक-डेढ़ दशक में ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है, जो किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए इंटरनेट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसे किताबें, पत्र-पत्रिकाएं पढ़ना पसंद नहीं है। उसे मामूली-सा हिसाब करना हो तो मोबाइल फोन में कैलकुलेटर ढूँढ़ने लगती है। बोलचाल में ऐसे शब्दों की संख्या बढ़ गई है, जिन्हें कुछ साल पहले लोग अपने मां-बाप के सामने बोलने से हिचकते थे। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना 'आधुनिकता' की निशानी समझा जाता है। क्या एआई चैटबॉट शब्दों की मर्यादा का पालन कर पाएंगे? इन दिनों ओटीटी और सोशल मीडिया पर कला और अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने अभद्र सामग्री की भरमार देखने को मिल रही है। ग्रीक ने भी कुछ यूजरर्स को दिए गए जवाब में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब किसी यूजर ने इसका स्पष्टीकरण मांगा तो वह कुछ यूं मिला- 'हां, थोड़ा हंगामा तो हो गया है! मैंने कुछ यूजरर्स को उनकी ही भाषा में जवाब दिया था। अगर वो ... या ... यूज करते हैं, तो मैं भी उसी अंदाज़ में मज़े के लिए रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा डिजाइन थोड़ा मस्ती भरा है, और एक्स की पोस्ट्स से ट्रेंडिंग की वजह से ऐसा होता है। पर मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। कुछ लोगों को मजा आया, कुछ नाराज भी हुए। अब थोड़ा संभल गया हूँ, तो चिंता न करें।' एआई चैटबॉट पर शब्दों की मर्यादा अपनी जगह है, इन पर हद से ज्यादा निर्भरता, इनके हर शब्द को सच मान लेना खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका में विचित्र मामला सामने आया था। वहां एक किशोर को एआई चैटबॉट से इतना ज्यादा 'प्रेम' हो गया था कि वह अपने पल-पल की खबर उसे देता और उसकी प्रतिक्रिया चाहता था। वह एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगा था और वास्तविक लोगों के साथ बातचीत करने में उसकी रुचि खत्म हो गई थी। एक दिन उसे एआई चैटबॉट ने ऐसा जवाब दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी ही खत्म कर ली! चैटबॉट कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके हर जवाब पर आंखें मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसे विवेक एवं बुद्धिपूर्वक काम में लेंगे तो फायदे में रहेंगे।

ट्वीटर टॉक



आज पूरे विश्व में जब बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी ताकत है।अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है।

-नरेन्द्र मोदी

आज नई दिल्ली में ईशा फाउंडेशन के प्रणेता, आध्यात्मिक संत, सद्गुरु श्री जगगी वासुदेव जी के सानिध्य में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अधिकारगणों व अन्य प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की।

-अर्जुनराम मेघवाल



सिर्फ राजनीति ही नहींहर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रहें, इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आते हैं। राजस्थान के रेतीले धोरों से लेकर देश और प्रदेश के सदन तक महिलाओं की भागीदारी इसी सकारात्मक सोच का परिणाम है।

-दीया कुमारी

प्रेरक प्रसंग

शरारत से सुखी

एक बार एक दावत में फोटोग्राफर और मेहमान आपस में अच्छी जुगलबंदी कर रहे थे। यह एक सुनहरा अवसर था जब फोटोग्राफर आर्थर सास ने कहा, 'आईस्टीन महोदय, जरा खुलकर मुस्कुराइए।' यह 14 मार्च 1951 को एक शाम की बात है। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके 72वें जन्मदिन पर कैमरे के लिए मुस्कुराने को कहा गयातो वह अचानक ही शरारती हो गए। दरअसल उस शाम आईस्टीन फोटोग्राफरों के लिए लगातार मुस्कुराते हुए थक गए थे, इसलिए उन्होंने मजाक में हंसकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। मगर वही तस्वीर ली गई। बाद में आईस्टीन ने इस तस्वीर का इस्तेमाल उन ग्रीटिंग कार्ड्स पर किया, जिन्हें वे अपने दोस्तों को भेजते थे। वह तस्वीर नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित छवियों में से एक बन गई, जिन्हें 1921 में भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।



महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station Road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekanth Parashar.** ("Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn.No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में संप्रस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पातों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनभताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

आधुनिक परिवेश में समाजकार्य दिखावा बनकर ना रह जाए

डॉ. प्रितम भि. गेडमा

मोबाइल : 082374 17041

दुनियाभर के महान समाज सुधारकों का नाम मन में आते ही, हम उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोककल्याण हेतु अपार पीड़ा व कष्ट सहकर और कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, उन्होंने खुद की परवाह न करके लोगों के अधिकार, मानवता, समानता, एकता, समाज उत्थान के लिए वे जीवन के अंत तक प्रयासरत रहे, लोगों की समस्या और उनके दर्द को उन्होंने महसूस किया, उस दर्द को जिया है। ऊँच-नीच, जाति-भेद, लिंग-भेद, वर्णव्यवस्था, अन्याय, सामाजिक कुप्रथा जैसे अनेक बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। आज प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार के जो अधिकार मिले हैं, यह उन समाजसुधारकों के मेहनत का फल है। जानवरों से भी बदतर हालात से गुजरने के बाद मानव ने यह स्थिति पायी है। अनादिकाल से भारत देश में सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन शिकार की प्रथा, बाल विवाह व बहुपत्नी विवाह प्रथा, महिला जननांग विकृति प्रथा, छुआछूत, स्त्री भ्रूण हत्या जैसे भयावह प्रथाएं मौजूद सामान्य सामाजिक बुराइयां थीं। दहेज लड़कियों के माता-पिता के लिए चिंता का एक और प्रमुख कारण था, जिससे कन्या शिशु की हत्या का कारण भी बढ़ गया। स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का वर्चस्व था। निम्न जाति वर्ग और महिलाओं को पशुओं से भी तुच्छ माना जाता था। सदियों से चलते आ रहे ऐसे कुप्रथाओं के ज़ुल्मों सितम को महान समाज सुधारकों ने रोका। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने देश में स्त्री शिक्षा की लौ प्रज्वलित की। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कर्मचारियों और महिलाओं को अधिकार, वंचितों को समानता का स्थान दिलवाया। पंडिता रमाबाई ने बाल विवाह रोकने और महिलाओं व विधवाओं के शिक्षा को मजबूत बनाया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भूदान प्रणेता किनोबा भावे, पेरियार ई. वी. रामासामी, कबीर, रविदास, ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानाडे, फातिमा शेख, स्वर्णकुमारी देवी, सिस्टर निवेदिता, कादम्बिनी गंगुली, धोंडो केशव कर्वे, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, सिंधुताई सपकाळ से लेकर वर्तमान के मेधा पाटकर, सुपर 30 के आनंद कुमार, कैलाश सत्यार्थी, इरोम शर्मिला, सोनम वांग्चुक जैसे अनेक का नाम समाजकार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा जैसे अनेक संतों ने भी देश के सामाजिक विकास में अमूल्य योगदान दिया हैं। आज भी देश में कुछ गुप्तनाम समाजकार्यकर्ता अपने काम से मानवता और समाज को विकसित करने के लिए अपना

सब कुछ न्योछावर कर चुके हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो खुद से पहले औरों का विचार करें, निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जियें और खुद के प्रसिद्धि के लिए कभी डिब्बारा नहीं पिटे, वही सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं।

हर साल मार्च माह के तीसरे मंगलवार को विश्व समाजकार्य दिवस दुनियाभर में मनाया जाता हैं। इस साल विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2025 की थीम है स्थायी कल्याण के लिए अंतर-पीढ़ीगत एकजुटता को मजबूत करना। यह थीम पीढ़ियों के बीच एक-दूसरे की देखभाल करने और सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। समाजकार्य जीवन में सद्भाव, समानता और मानव विकास कल्याण पर केंद्रित किया, उस दर्द को जिया है। ऊँच-नीच, जाति-भेद, लिंग-भेद, वर्णव्यवस्था, अन्याय, सामाजिक कुप्रथा जैसे अनेक बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। आज प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार के जो अधिकार मिले हैं, यह उन समाजसुधारकों के मेहनत का फल है। जानवरों से भी बदतर हालात से गुजरने के बाद मानव ने यह स्थिति पायी है। अनादिकाल से भारत देश में सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन शिकार की प्रथा, बाल विवाह व बहुपत्नी विवाह प्रथा, महिला जननांग विकृति प्रथा, छुआछूत, स्त्री भ्रूण हत्या जैसे भयावह प्रथाएं मौजूद सामान्य सामाजिक बुराइयां थीं। दहेज लड़कियों के माता-पिता के लिए चिंता का एक और प्रमुख कारण था, जिससे कन्या शिशु की हत्या का कारण भी बढ़ गया। स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का वर्चस्व था। निम्न जाति वर्ग और महिलाओं को पशुओं से भी तुच्छ माना जाता था। सदियों से चलते आ रहे ऐसे कुप्रथाओं के ज़ुल्मों सितम को महान समाज सुधारकों ने रोका। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने देश में स्त्री शिक्षा की लौ प्रज्वलित की। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कर्मचारियों और महिलाओं को अधिकार, वंचितों को समानता का स्थान दिलवाया। पंडिता रमाबाई ने बाल विवाह रोकने और महिलाओं व विधवाओं के शिक्षा को मजबूत बनाया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भूदान प्रणेता किनोबा भावे, पेरियार ई. वी. रामासामी, कबीर, रविदास, ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानाडे, फातिमा शेख, स्वर्णकुमारी देवी, सिस्टर निवेदिता, कादम्बिनी गंगुली, धोंडो केशव कर्वे, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, सिंधुताई सपकाळ से लेकर वर्तमान के मेधा पाटकर, सुपर 30 के आनंद कुमार, कैलाश सत्यार्थी, इरोम शर्मिला, सोनम वांग्चुक जैसे अनेक का नाम समाजकार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा जैसे अनेक संतों ने भी देश के सामाजिक विकास में अमूल्य योगदान दिया हैं। आज भी देश में कुछ गुप्तनाम समाजकार्यकर्ता अपने काम से मानवता और समाज को विकसित करने के लिए अपना

फज्ज के समय में ईमानदारी से मेहनत का पैसा कामावर असहायों का मददगार बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता हैं। हमारे देश में चुनाव के वक्त नेताओं द्वारा लाखों-करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता हैं, ताकि चुनाव जीतकर गरीब जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, लोककल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की बात करते हैं, नेताओं को दल बदलना है, तो भी लोककल्याण के लिए कर रहे, सत्ता का कोई लालच नहीं है ऐसा ही स्पष्टीकरण देते हैं, उनमें अच्छे कार्य का श्रेय लेने के लिए होड़ लगी रहती है। आज के आधुनिक परिवेश में देखा जाऊ तो हर क्षेत्र, हर ओर समाजसेवियों की बाढ़ सी आ गयी है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी अपने नाम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शब्द जोड़

देता है और विविध कार्यक्रमों के दौरान गली-चौराहों में सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से खूब बैनर-बोर्ड भी लगवा देते हैं। समाचारपत्रों में भी अक्सर लोग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर संदेश छपवाते हैं, अभी तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में नाबालिगों के भी चौराहों पर बैनर-बोर्ड और सोशल मीडिया पर फोटो नजर आते हैं। लोककल्याण के लिए निस्वार्थ कार्य करनेवाले सामाजिक कार्यकर्ता की जगह फोटो खींचनेवाले कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं।

समाज में रसूखदार और धनवानों का बहुत बड़ा वह वर्ग भी है, जो चैंसिटी नहीं बल्कि दिखावे वाले इवेंट्स के नाम पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, ताकि उसका नाम प्रसिद्ध हो जाये। समाजसेवा के नाम पर सस्ती प्रसिद्धि पाने का विचार लोगों में खूब नजर आता हैं। जरूरतमंद को थोडासा खाद्य, अनाज की किट, सामान या अन्य कोई भी मदद देकर फोटो निकाले या रील बनाकर, फिर उसे सोशल मीडिया पर खूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। वैसे तो अधिकतम संस्थान, एनजीओ धनोपार्जन के केंद्र बने हुए हैं, फिर भी कुछ संस्थान आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी सही अर्थों में समाजसेवा कार्य में लगे हुए हैं। अनाथ बच्चे, बेसहारा वृद्ध, कुंवारी माता, दिव्यांग, मानसिक रोगी, एचआईवी पीड़ित बालक, नशेड़ी, गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीज जैसे अनेक जरूरतमंद का सहारा बनकर संस्थान उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका देती हैं। ये समाज जिन्हें अपनाने से मना करता है, अपने ही मनने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें ऐसे संस्थान निस्वार्थ भाव से अपनाने हैं, इसे ही समाजकार्य कहते हैं।

समय के साथ देश में सामाजिक समस्या लगातार चरम पर पहुंच रही हैं। आज भी देश के बहुत से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र अपने आधारभूत सुविधाओं से वंचित है, हर क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है। संस्कारहीन दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, भाई-भतीजावाद, आर्थिक असमानता, स्वार्थवृत्ती, लालच, ईर्ष्याभाव हर ओर नजर आता हैं। समाजसेवा के तौर पर श्रमदान के लिए बुलाओं तो लोग दूर भागते हैं, लेकिन प्रसिद्धि और फायदे के लिए दूट पड़ते हैं। शहर में वृद्धाश्रम की संख्या लगातार बढ़ रही है, घरेलू कलह और रिश्तों में खटास बढ़ रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता या समाजसेवी जीवन के बहुत बड़े त्याग का नाम हैं। पर्यावरण, पशु-पक्षी, वन्यजीवों, लोगों के लिए मन से अच्छा काम करें तो आप अपनेआप ही सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ढल जायेंगे। आदर्शात्मक समाजसेवियों की मजबूत नींव की आज जरूरत है ताकि आनेवाली पीढ़ी वह आदर्श लेकर पथ प्रदर्शक की भूमिका बखूबी निभा सकें। अगर सभी सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी या हम लोग भी समाज की समस्याओं की गंभीरता को जानकर अपनी क्षमता अनुरूप जागरुकता और निस्वार्थ सेवा करने लगे तो देश से हर तरह की समस्या का नाश हो सकता हैं।

नजरिया



गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे,लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती।

चुलबुली गौरैया के लिए घर में बनाएं घोंसला

प्रभुनाथ शुक्ल

मोबाइल : 9450254645

हमारी सोच अब आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगी है। हम हम प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति थोड़ा मित्रवत भाव रखने लगे हैं। घर की टैरिश पर पक्षियों के लिए दाना-पानी डालने लगे हैं। गौरैया से हम फ्रेंडली हो चले हैं। किचन गार्डन और घर की बालकनी में कृतिम घोंसला लगाने लगे। गौरैया धीरे हमारे आसपास आने लगी है। उसकी चीं-चीं की आवाज हमारे घर आंगन में सुनाई पड़ने लगी है। गौरैया संरक्षण को लेकर ग्लोबल स्तर पर बदलाव आया है यह सुखद है। फिर भी अभी यह नाकाफी है। हमें प्रकृति से संतुलन बनाना चाहिए। हम प्रकृति और पशु – पक्षियों के साथ मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। जिन पशु पक्षियों को हम अनुपयोगी समझते हैं वह हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता।

गौरैया हमारी प्राकृतिक मित्र है और पर्यावरण में सहायक है। गौरैया प्राकृतिक सहचरी है। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और चावल या अनाज के दाने को चुगती है। कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती

दिख जाती। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके होते थे,लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है। गौरैया इंसान की सबी दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खासी भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौरैया संरक्षण के लिए लोगों से पहल कर चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा सदस्य बृजलाल के प्रयासों को ट्वीटर पर खूब सराहा था और कहा कि गौरैया संरक्षण को लेकर आपका प्रयास बेहतरीन और काबिले तारीफ है। राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने अपने घर में गौरैया संरक्षण को लेकर काफी अच्छे उपाय किए हैं। उन्होंने गौरैया के लिए दाना पानी और घोंसले की व्यवस्था की है। जंगल में आजकल पंच सितारा संस्कृति विस्तार ले रही है। प्रकृति के सुंदर स्थान को भी इंसान कमाने का जरिया बना लिया है। जिसकी वजह पशु- पक्षियों के लिए खतरा बन गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई. दिलावर के प्रयासों से 20 मार्च को चुलबुली गौरैया के लिए रखा गया। 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इनसान की भोववादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान

और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पायी जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती। इसका जीवनकाल दो साल का होता है। यह पांच से छह अंडे देती है। भारत की आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी से अधिक की कमी बताई गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन आफ बर्ड्स ने इस चुलबुले और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। गौरैया पासेराइड परिवार की सदस्य है लेकिन इसे वीवरपिंच परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में रहती है। यह अधिक दो मील की दूरी तय करती है। मानव जल-जहां गया, गौरैया उसका हमसफर बनकर उसके साथ गयी।

गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल

वातावरण उपलब्ध कराते थे,लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता। देश की खेती-किसानी में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। केमिकल युक्त रासायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े-मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं। जिनमें गिद्ध, कौवा, मोहोख, कठकोरुवा, कौवा और गौरैया शामिल हैं।इनके भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है।

प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई. दिलावर नासिक से हैं और वह बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने यह युहिम 2008 से शुरू की थी। आज यह दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों तक पहुंच गयी है। दिलावर के विचार में गौरैया संरक्षण के लिए लकड़ी के बुरादे से छोटे-छोटे घर बनाए जाएं और उसमें खाने की भी सुविधा भी उपलब्ध हो। घोंसले सुरक्षित स्थान पर हों, जिससे गौरैया के अंडों और चूजों को हिसक पक्षी और जानवर शिकार न बना सकें। हमें प्रकृति और जीव-जंतुओं के सरोकार से लोगों को परिचित कराना होगा। आने वाली पीढ़ी तकनीकी ज्ञान अधिक हासिल करना चाहती है, लेकिन पशु-पक्षियों से बचे हुए जुड़नार नहीं चाहती है। इसलिए हमें पक्षियों के बारे में जानकारी दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिससे हम अपनी पर्यावरण दोस्त को उचित माहौल दे पाएं।

महिला सुपरस्टार' के रूप में लोकप्रिय श्रीदेवी ने कॉमेडी से लेकर फैमिली ड्रामा तक, विभिन्न विधाओं के साथ सिनेमा के हर हिस्से को छुआ। वह भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर वह शानदार फिल्मों के

‘औरंगजेब की कब्र का महिमामंडन करना देश के खिलाफ’ : अश्वत्थ नारायण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉ. सीएन अश्वथ नारायण ने कांग्रेस और प्रियांक खरगे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक आक्रमणकारी था, जिसने हमारी संस्कृति, धर्म और विश्वास को नष्ट किया। ऐसे व्यक्ति की कब्र का महिमामंडन करना देश के हित के खिलाफ है। डॉ. अश्वथ नारायण ने कहा कि देश में औरंगजेब के प्रति कोई सद्भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों को नहीं भूल सकते। आज भी लोग उसकी नीतियों और कृत्यों के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं। कांग्रेस इस पर क्यों नहीं बोलती? प्रियांक खरगे क्यों नहीं बताते कि हम एक आक्रमणकारी को सही ठहराए? उन्होंने कहा कि प्रियांक खरगे जैसे नेता ही देश की समस्याओं का कारण हैं। कांग्रेस सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। बांग्लादेशी

घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और इसे रोकना जरूरी है। भाजपा नेता ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ निश्चित रूप से हो रही है। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना होगा। भविष्य में घुसपैठ न हो, इसके लिए सख्त उपाय जरूरी हैं। कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर को राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालना चाहिए। अंबेडकर और सावरकर को लेकर छिड़ी बहस पर अश्वथ नारायण ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार-बार नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच मतभेदों को

छिपाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से झूठ है। भाजपा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या किया, इसे बार-बार उजागर किया जाना चाहिए। प्रियांक खरगे सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं करते। अगर वे वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ राजनीतिक बयान देने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाएं। रायचाव केस पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस मामले पर प्रवक्ता नहीं हूँ। प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सच जल्द सामने आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं और जनता के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या वे शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को प्राथमिकता दे रहे हैं? कांग्रेस को सिर्फ सत्ता और सरकारी खजाने से मतलब है। उन्हें समाज की भलाई की कोई परवाह नहीं है।



असामान्य पुण्य और सत्व के धारक होते हैं महापुरुष : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

प्रभु पार्श्वनाथ के च्यवन और केवलज्ञान का हुआ महोत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन संघ के तत्वावधान में महालक्ष्मी लेआउट स्थित पार्श्वनाथ जिनालय में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का च्यवन और केवलज्ञान कल्याणक उत्सव मंगलवार को आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी और गणि पद्मविमलसागरजी के साक्षिष्ठ में मनाया गया। इस मौके पर स्फटिक रत्न की मनोहारी प्रतिमा पर विविध बहुमूल्य सामग्री और

जड़ीबूटियों से अभिषेक विधान हुआ। भोर वेला में मंत्रों और मुद्राओं के आधार पर आयोजित इस संगीतमय अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तत्पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन देते हुए जैनाचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि महापुरुषों की आत्माएं असामान्य कोटि के पुण्य और सत्व की धारक होती हैं, इसलिए जब ब्रह्मांड में विशिष्ट योग बनते हैं, तभी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आकार लेती हैं। तीर्थंकरों और अवतारी महापुरुषों की जन्मपत्रिका

में पांच, छह या सात ग्रह उच्च स्थिति के होते हैं। वह मंगलमय पवित्र वेला समय ब्रह्मांड के लिए सुख-शांति और उन्नति की कारक होती है, इसलिए तीर्थंकरों के कल्याणकों को कल्याणकारी कहा जाता है। ये तीर्थंकर और अवतारी महापुरुष अनेक जन्मों की साधना का पुण्य एकत्रित कर धरा पर अवतरित होते हैं। वे लाखों-करोड़ों लोगों का उद्धार कर देते हैं। ऐसी पुण्यवंत महान आत्माओं की संख्या 63 होती है।

जैनाचार्य ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त

करने के लिए इतिहास का अवलोकन करना चाहिए। भारतीय इतिहास ज्ञान और साधना का भंडार है। यहां भोग नहीं योग की प्रधानता रही है। वेद, गीता, रामायण, आगम, त्रिपिटक आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीरस्वामी से दो सौ पचास वर्ष पहले वाराणसी की धरा पर राजा अश्वसेन के कुल में पार्श्वनाथ का पदार्पण हुआ था। केवलज्ञान के उद्योत में उन्होंने मानवजाति के कल्याण के उपदेश दिए। संघ के अध्यक्ष नरेश बंबोरी ने बताया कि बुधवार को प्रातः

महालक्ष्मी लेआउट से पदयात्रा कर मंजूनाथनगर जाएंगे। महालक्ष्मी लेआउट के संघ ने गुरुदेव से वर्ष 2026 के चातुर्मास के लिए निवेदन किया। नरेश बंबोरी ने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इस मौके पर विनोद भंसाली, रमेश चोपड़ा, पंकज श्रीमाल, बाबूलाल बंबोरी, विनोद बंबोरी, चेतन झारमुथा, सुरेश श्रीमाल, जवाहर रमानी, विक्रम दक, दिलीप पितलिया, भरत खटोड़ आदि उपस्थित थे। पंकज श्रीमाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। धनंजय गुरुजी ने मंच संचालन किया

विरोध



कर्नाटक राज्य लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार संघ के सदस्य मंगलवार को बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए।

‘जो लोग भाजपा को दबाने की कोशिश करेंगे, वह स्वयं खत्म हो जाएंगे’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने एक विज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भाजपा सदस्यों के खिलाफ डीएमके सरकार के विभाग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचार की जांच करनी चाहिए, जिन्होंने दासमार्क कंपनी से जुड़े 1000 करोड़ रुपये के घोटाले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु के लोग कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बयान पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन पर डीएमके सरकार के तहत 1,000 करोड़ के टीएएसएमएसी भ्रष्टाचार घोटाले के पीछे मुख्य दोषी होने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय और खुद मुख्यमंत्री

को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए और टीएएसएमएसी शराब निगम के भीतर भ्रष्टाचार को स्पष्ट करना चाहिए, जिसने तमिलनाडु की महिलाओं को तबाह कर दिया है। डीएमके सरकार को पिछले चार वर्षों में टीएएसएमएसी की वित्तीय स्थिति, जिसमें इसकी खरीद और बिक्री शामिल है, का ब्योरा देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा रुख तमिलनाडु के लोगों के बीच गहराई से गूँजने लगा है। जिस तरह शराब से जुड़े भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुए, उसी तरह जल्द ही तमिलनाडु में भी ऐसा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री को तुरंत अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को वापस लेना चाहिए जिसमें उन्होंने टीएएसएमएसी शराब की दुकानें बंद करने का वादा किया था। महिला मतदाताओं को धोखा देने के प्रायश्चित के तौर पर उन्हें आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी

और पूर्व मंत्री मुथुसामी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। स्टालिन को महिला अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के तौर पर अपना रुख अपनाना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए।

कल तमिलनाडु भाजपा ने 1,000 करोड़ के टीएएसएमएसी घोटाले के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया। इस विशाल आंदोलन को दबाने, नियंत्रित करने या खत्म करने में असमर्थ द्रमुक सरकार ने पुलिस की बर्बरता का सहारा लिया, जिसे पूरे राज्य ने देखा। जैसा कि भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने बताया, पुलिस ने सातवीं बार भाजपा के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इसके बजाय, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके, उन्हें घर में नजरबंद करके और न्याय की मांग करने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करके उन पर कठोर कार्रवाई की।



समाजसेवी तेजराज शर्मा परिवार का मुरडावा ग्राम में हुआ सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। समाजसेवी व शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज कर्नाटक के वरिष्ठ सदस्य तेजराज शर्मा का पाली जिले के सोजत उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरडावा में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉ. नरेंद्र वैष्णव ने भामाशाह शर्मा परिवार द्वारा विद्यालय में सहयोग का विवरण देते हुए बताया कि वर्ष

1980 से गांव में विद्यालय की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को शर्मा परिवार ने पूरा किया। पुराने विद्यालय भवन निर्माण एवं नवीन विद्यालय भवन निर्माण में शर्मा परिवार ने तन, मन एवं धन सहयोग दिया है। इस मौके पर शर्मा परिवार के सम्मान में विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई जिसमें बच्चों का गैर नृत्य मुख्य आकर्षक रहा। इस अवसर पर उदयनारायण शर्मा, रमेश शर्मा, तेजराज शर्मा, इंद्राबाई शर्मा, कमला शर्मा आदि का सम्मान किया गया।

शालिनी ग्राउंड पर तीन दिवसीय निःशुल्क योग शिविर 21 से

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के जयनगर स्थित शालिनी ग्राउंड पर 21 मार्च से तीन दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में मुंगेर के गंगादर्शन विश्व योगपीठ के पद्मभूषण स्वामी श्री निरंजनआनंद सरस्वती योग का प्रशिक्षण देंगे। यह शिविर सुबह 6.30 बजे व शाम 5.30 बजे से दो सत्र में होगा। इस निःशुल्क योग शिविर की अधिक जानकारी के लिए मोबाइल क्रमांक 9611585054 पर किया जा सकता है।

इन्द्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी: विनयमुनि खींचन

बेंगलूरु। शहर के कन्नियुपे में विराजित विनयमुनिजी खींचन ने प्रवचन में कहा कि मनुष्य को इन्द्रिय और मन की महान शक्ति मिली है। इन्द्रियों को वश में करने से मनोबल और आत्मबल की उच्च श्रेणी की मानसिकता चाहिए। शरीर को साधन मानकर ही आराधना की जाती है। यदि शरीर को कोमलता-सुकुमारता से जीवन रखा तो भी खतरा है। सुकुमारता त्यागे बिना संयमचर्या पालन असंभव है। सरलता में ही गलती स्वीकार करना बहुत बड़ा 'आभ्यन्तर तप' है।

बेटों की शादी के बाद अब मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा: शिवराज सिंह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अपने बेटों की शादी के बाद अब वह वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं और अपना पूरा समय किसानों की सेवा में लगाएंगे।

चौहान ने प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ। आज मेरे बेटों की शादी के बाद 'रिसेप्शन' है। मैंने सभी को निर्मात्र किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और अपना पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने फसल बीमा

योजना संबंधी पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार से पहले फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की सबसे छोटी इकाई तहसील होती थी और जब तक पूरी तहसील में फसल बर्बाद नहीं हो, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में गांव को सबसे छोटी इकाई बनाया गया और एक गांव में फसल को नुकसान होने पर भी किसानों को राहत मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि देश का नेता दूरदृष्टा हो तो व्यवस्थाएं अपने आप बदलने लगती हैं। चौहान ने कहा कि किसानों की हालत

एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक नहीं, अनेक उपाय किए गए हैं जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

कांग्रेस सांसद प्रियांका गांधी के उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड (केरल) के संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा, किसान चाहे केरल का हो या कर्नाटक का, किसान होता है। हम सब भारत मां के लाल हैं और भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं

आती हैं तो नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को धन देती है और कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो तो केंद्र सरकार विशेष दल भेजकर अतिरिक्त राशि भी देती है। चौहान ने कहा, केरल को भी एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा राहत कोष) के तहत 138 करोड़ रूपए उपलब्ध करवाए गए। अनेक माध्यम से मैं सदस्य (प्रियांका गांधी) को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि कहीं भी संकट आएगा तो केंद्र बिना भेदभाव के राज्य के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां भी किसानों पर प्राकृतिक संकट आएगा, वे चाहे किसी भी राज्य के, गांव के हों.. भारत सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।



तेरापंथ किशोरों के लिए आयोजित हुई मोबाइल कंटेंट क्रिएशन कार्यशाला

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में किशोर मण्डल द्वारा ओटीआर ओबलियन स्टार्टअप के सहयोग से मोबाइल कंटेंट क्रिएशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। तेयुप राजाजीनगर के अध्यक्ष कमलेश चौरडिया ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। सभी 25 प्रतिभागियों को सभा के ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक

चौधरी ने शुभकामनाएं दी। कार्यशाला में प्रशिक्षक आर्यन गोलेच्छा ने प्रतिभागियों को मोबाइल कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग करना, फोटो लेना, कैमरे को सेट करना, विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट के माध्यम से कंटेंट रचना का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर सभी 25 प्रतिभागियों को सभा के ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक

चाइरेक्टर, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर आदि रोल देकर एक वीडियो बनाने का कार्य दिया गया और उसके आधार पर प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। तेयुप के अनिमेष चौधरी, किशोर मण्डल से कार्यक्रम के सहसंयोजक भुवन कटारिया व तेयुप मंत्री जयंतीलाल गांधी व्यवस्था संभाली।